रजिस्टर्ड नं० पी०/एस० एम० 14

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, मंगलवार, 24 मार्च, 1981/3 चैत्र, 1903

हिमाचल प्रदेश सरकार

विधान सभा सचिवालय

अधिसूचनाएं

शिमला-171004, 24 मार्च, 1981

संख्या-1-12/81-वि० स०.—हिमाचल प्रदेश विधान सभा प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 135 के अन्तर्गत, दी हिमाचल प्रदेश जनरल सेल्ज टैक्स (अमैन्डमैन्ट) बिल, 1981 (बिल नं 1 आफ 1981)

466-राजपत्र-24-3-81—1,013.

मूल्यः 20 पैसे।

जो हिमाचल प्रदेश विधान सभा में 23 मार्च, 1981 को पुर:स्थापित किया गया है, सर्व साधारण की सूचनार्थ राजपत्र, में मुद्रित करने के लिए प्रेषित किया जाता है ।

राज कुमार महाजन,
सचिव

Bill No. 1 of 1981.

THE HIMACHAL PRADESH GENERAL SALES TAX (AMENDMENT) BILL, 1981

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh General Sales Tax Act, 1968 (*Act No.* 24 *of* 1968).

BE it enacted by the Legislative Assembly of the Himachal Pradesh in the Thirty-second Year of the Republic of India as follows:—

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Himachal Pradesh General Sales Tax (Amendment) Act, 1981.

(2) It shall be deemed to have come into force on the 15th day of November, 1980.

Amendment of section 4.

24 of 1968

2. In clause (e) of sub-section (6) of section 4 of the Himachal Pradesh General Sales Tax Act, 1968 (hereinafter called the principal Act), for the figures "40,000" the figures "1,00,000" shall be substituted.

Amendment of section 12.

3. In the existing proviso to sub-section (4) of section 12 of the principal Act—

(*a*) after the words "through a" but before the words "bank draft", the words "crossed cheque or" shall be inserted; and

(*b*) for the sign "." occurring at the end the sign ":" shall be substituted and thereafter the following proviso shall be added, namely:—

"Provided further that where the payment is made through a crossed cheque and the cheque is dishonoured, the dealer shall be deemed to have not made the payment and shall be liable to any action which may be taken for not making payment under the Act or the rules framed thereunder."

Repeal and savings.

5 of 1980

4. (1) The Himachal Pradesh General Sales Tax (Amendment) Ordinance, 1980 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the said Ordinance shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act, as if this Act had come into force on the day on which such thing was done or action was taken.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

This Bill is designed to replace without any modification the Himachal Pradesh General Sales Tax (Amendment) Ordinance, 1980 (Himachal Pradesh Ordinance No. 5 of 1980) which was promulgated by the Governor, Himachal Pradesh on the 14th November, 1980 and published in the Rajpatra, Himachal Pradesh, on the 15th November, 1980, to provide relief to the small traders of this Pradesh by enhancing the sales tax assessment limit from Rs. 40,000 to rupees one lac and to facilitate the payment of sales tax through crossed cheques by making the necessary amendments in the principal Act.

This Bill seeks to achieve the above object.

GUMAN SINGH CHAUHAN,
Minister-in-charge.

SIMLA:
The 23rd Marh, 1981.

FINANCIAL MEMORANDUM

The provisions proposed in clause 2 of the Bill, when enacted, will provide tax relief to the small traders whose annual taxable turnover does not exceed Rs. 1,00,000. At present tax relief is available to the small traders whose annual taxable turnover does not exceed Rs. 40,000. This measure is likely to reduce the income to the State exchequer to the tune of Rs. 60,00,000 per annum.

MEMORANDUM ON DELEGATED LEGISLATION

Nil

RECOMMENDATIONS OF THE GOVERNOR UNDER ARTICLE 207 OF THE CONSTITUTION OF INDIA

[File No. EXN.F(10)-8/77– Excise and Taxation Department]

The Governor of Himachal Pradesh, after having been informed of the subject matter of the Himachal Pradesh General Sales Tax (Amendment) Bill, 1981, recommends under Article 207 of the Constitution of India, the introduction and consideration of the Bill in the Legislative Assembly.

शिमला-171004, 24 मार्च, 1981

संख्या-1-10/81-वि0 स0.—हिमाचल प्रदेश विधान सभा प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 135 के अन्तर्गत, दा हिमाचल प्रदेश एक्सटैन्शन आफ ला एण्ड रिपीलिंग बिल, 1981 (बिल नं0 3 आफ 1981) जो हिमाचल प्रदेश विधान सभा में 23 मार्च, 1981 को पुरःस्थापित किया गया है, सर्वसाधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने के लिए प्रेषित किया जाता है।

राज कुमार महाजन,
सचिव।

1981 का विधेयक संख्यांक 3

हिमाचल प्रदेश विधि विस्तारण तथा निरसन विधेयक, 1981

(विधान सभा में यथा पुरःस्थापित)

हिमाचल प्रदेश में प्रथम नवम्बर, 1966 से शीघ्र पूर्व समाविष्ट क्षेत्रों में प्रयोज्य अथवा प्रवृत कतिपय विधियों का पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा 5 के अधीन हिमाचल प्रदेश में परिवर्धित क्षेत्रों पर विस्तारण के लिए उपबन्ध करने तथा कतिपय अधिनियमितियों की हिमाचल प्रदेश राज्य में प्रयुक्ति का निरसन करने हेतु

विधेयक

भारत गणराज्य के बत्तीसवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्न रूप में यह अधिनियमित हो, —

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ।

1. (1) यह अधिनियम हिमाचल प्रदेश विधि विस्तारण तथा निरसन अधिनियम, 1981 कहलायेगा।

(2) यह तत्काल प्रवृत होगा।

परिभाषाएं

2. इस अधिनियम में, जब तक कि कोई बात विषय या सन्दर्भ में विरुद्ध न हो, —
(क) "शासकीय राजपत्र" से अभिप्रेत है—राजपत्र हिमाचल प्रदेश;
(ख) "पुराने क्षेत्रों" से अभिप्रेत है—प्रथम नवम्बर, 1966 से तत्काल पूर्व हिमाचल प्रदेश में समाविष्ट क्षेत्र;
(ग) "अनुसूची" से अभिप्रेत है—इस अधिनियम से संलग्न अनुसूची;
(घ) "राज्य सरकार" से अभिप्रेत है, हिमाचल प्रदेश सरकार; तथा
(ङ) अन्तरित राज्य क्षेत्रों से अभिप्रेत है, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा 5 के अधीन हिमाचल प्रदेश में जो राज्य क्षत्र परिवर्धित किए गए थे। 31 of 1966

कतिपय विधियों का अन्तरित क्षेत्रों में विस्तारण।

3. अनुसूची–I में विनिर्दिष्ट, समय समय पर यथासंशोधित, अधिनियमिति जो पुराने क्षेत्रों को प्रयोज्य है अथवा उसमें प्रवृत है तथा तदधीन बनाये गये सब नियम, विनियमन, अधिसूचनाएं, आदेश तथा उपविधियां तथा जारी किए गए सब निदेश अथवा अनुदेश जो इस अधिनियम के प्रारम्भ होने से तुरन्त पूर्व प्रवृत हैं एतद्द्वारा अन्तरित राज्य क्षेत्रों में विस्तारित किए जाते हैं तथा उसमें प्रवृत होंगे।

कतिपय निर्देशों का अर्थान्वयन।

4. धारा 3 में यथानिर्दिष्ट अधिनियमिति अथवा तदधीन बनाये गये नियमों, विनियमनों, अधिसूचनाओं, आदेशों तथा उपविधियों अथवा जारी किये गये निदेशों अथवा अनुदेशों में कोई निर्देश;—

(1) किसी विधि जो अन्तरित राज्य क्षेत्रों में प्रवृत नहीं है, से ऐसे राज्य क्षेत्रों के सम्बन्ध में समरूपी विधि, यदि कोई ऐसे राज्य क्षेत्रों में प्रवृत है, के लिए निर्देश से अर्थ लगाया जाए; तथा

(2) हिमाचल प्रदेश राज्य से, चाहे शब्दों के किसी भी रूप में हों, अन्तरित राज्य क्षत्रों के लिए अन्तर्भूत निर्देश से अर्थ लगाया जाएगा।

निरसन तथा व्यावृति।

5. यदि, इस अधिनियम के प्रारम्भ से तत्काल पूर्व, अन्तरित राज्य क्षेत्रों में उस अधिनियमिति अथवा तद्धीन बनाये गये किन्हीं नियमों, विनियमनों, अधिसूचनाओं, आदेशों तथा उपविधियों तथा जारी किए गए निदेशों अथवा अनुदेशों, जिनका उन राज्य क्षेत्रों पर धारा 3 द्वारा विस्तारण किया गया है, के समरूपी कोई विधि प्रवृत है, तो अनुसूची-II में विनिर्दिष्ट अधिनियमितियों सहित वह विधि इस अधिनियम के प्रारम्भ होने पर अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबन्धित के सिवाये निरसित मानी जाएगी :

परन्तु ऐसा निरसन,--

(क) इस प्रकार निरसित किसी विधि के पूर्व प्रवर्तन अथवा तद्धीन सम्यक रूप से की गई अथवा सहन की गई कोई बात ;

(ख) इस प्रकार निरसित किसी भी विधि के अधीन अर्जित, प्रोदभूत अथवा उपगत किसी अधिकार, विशेषाधिकार, वाध्यता अथवा दायित्व;

(ग) इस प्रकार निरसित ऐसी किसी विधि के विरुद्ध किए गए किसी अपराध की बाबत उपगत किसी शास्ति, समपहरण या दण्ड पर; अथवा

(घ) पूर्वोक्त जैसे किसी अधिकार, विशेषाधिकार, आभार, उत्तरदायित्व, शास्ति, समपहरण या दण्ड के सम्बन्ध में किसी अन्वेषण, विधिक कार्यवाही या उपचार पर ;

प्रभाव नहीं डालेगा, और ऐसा अन्वेषण, विधिक कार्यवाही, उपचार वैसे ही संस्थित किया जा सकेगा, और शास्ति, समपहरण या दण्ड वैसे ही अधिरोपित किया जा सकेगा मानो यह अधिनियम पारित नहीं किया गया था :

परन्तु यह और कि इस प्रकार निरसित किसी विधि के अधीन की गई कोई बात अथवा कोई कार्यवाही अन्तरित राज्य क्षेत्रों में धारा 3 द्वारा विस्तारित अधिनियमिति के समरूपी उपबन्धों के अधीन की गई मानी जाएगी तथा तदनुसार प्रवृत रहेगी जब तक कि इस प्रकार विस्तारित अधिनियमिति के अधीन की गई किसी बात अथवा किसी कार्यवाही द्वारा अधिक्रान्त नहीं की जाती है।

अनुसूची-I में विनिर्दिष्ट अधिनियमिति अथवा नियमों इत्यादि की प्रयोज्यता को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्यों के लिए न्यायालयों अथवा अन्य प्राधिकारियों की शक्तियां।

6. अनुसूची-I में विनिर्दिष्ट अधिनियमिति अथवा तद्धीन बनाये गये किसी नियम, विनियम, अधिसूचना, आदेश, उपविधि, निर्देश अथवा अनुदेश, जो धारा 3 में निर्दिष्ट है, की अन्तरित राज्य क्षेत्रों में प्रयोज्यता को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य के लिए कोई न्यायालय अथवा अन्य प्राधिकारी तत्वार्थ को प्रभावित किए बिना उसका ऐसे परिवर्तनों सहित जो इसे न्यायालय अथवा अन्य प्राधिकारी के समक्ष विषय में ग्रहण करने के लिए आवश्यक या उचित हो, अर्थ लगा सकता है।

नियम बनाने की शक्ति का अप्रभावित रहना।

7. इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट कोई भी बात राज्य सरकार अथवा किसी अधिकारी अथवा प्राधिकारी की अनुसूची–I में विनिर्दिष्ट अधिनियमिति के अधीन प्रयोक्तव्य, बनाये गय नियमों, विनियमनों, अधिसूचनाओं तथा उपविधियों और जारी किए गए निदेशों अथवा अनुदेशों जो धारा 3 द्वारा अन्तरित राज्य क्षेत्रों में विस्तारित किए गए हैं, में परिवर्धन करने, संशोधन करने, परिवर्तित करने अथवा विखण्डित करने की शक्ति को प्रभावित नहीं करेगी।

कठिनाइयां दूर करने की शक्ति।

8. यदि अनुसूची–I में विनिर्दिष्ट अधिनियमिति के उपबन्धों को अन्तरित राज्य क्षेत्रों में प्रवृत करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो राज्य सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचित आदेश द्वारा कठिनाई को दूर करने के लिए ऐसे उपबन्ध बना सकती है अथवा ऐसे निदेश दे सकती है जो उसे आवश्यक अथवा समीचीन प्रतीत हों।

अनुसूची – I

(धारा 3 देखें)

क्र0 सं0	वर्ष	अधिनियम की संख्या	अधिनियम का नाम
1	2	3	4
1.	1953	7	दा हिमाचल प्रदेश कम्पलसरी प्राइमरी एजुकेशन एक्ट, 1953.

अनुसूची–II

(धारा 6 देखें)

क्रम सं0	वर्ष	अधिनियम की संख्या	अधिनियम का नाम
1	2	3	4
1.	1825	11	अन्तरित राज्य क्षेत्रों में यथा प्रवृत दा बंगाल अल्युवियन एण्ड डिल्युवियन रैगुलेशन, 1825.
2.	1920	1	अन्तरित राज्य क्षेत्रों में यथा प्रवृत दा पंजाब लिमिटेशन (कस्टम) एक्ट, 1920.
3.	1920	1	भूतपूर्व बिलासपुर रियासत में यथा प्रवृत दा पंजाब लिमिटेशन (कस्टम) एक्ट, 1920.
4.	1931	2	अन्तरित राज्य क्षेत्रों में यथा प्रवृत दा पंजाब म्युनिसिपल (एक्जेक्यूटिव ओफिसरज़) एक्ट, 1931.
5.	1938	9	अन्तरित राज्य क्षेत्रों में यथा प्रवृत दा पंजाब डेटअरज़ प्रोटेक्शन (अमैण्डमैंट) एक्ट, 1938.
6.	1941	5	अन्तरित राज्य क्षेत्रों में यथा प्रवृत दा पंजाब जागीरज एक्ट, 1941.
7.	1941	14	दा ईस्ट पंजाब इलैक्ट्रीसिटी (अमरजैंसी पावरज़) एक्ट, 1941 जैसा कि अन्तरित राज्य क्षेत्रों में प्रवृत है।
8.	1948	11	दा पंजाब मोलैसीज (कन्ट्रोल) एक्ट, 1948 जैसा कि अन्तरित राज्य क्षेत्रों में प्रवृत है।
9.	1948	11	दा पंजाब मोलैसीईज (कन्ट्रोल) एक्ट, 1948 जो भारत सरकार, गृह मन्त्रालय, अधिसूचना संख्या ए0 यू0 4/7-61-जुड-II, दिनांक 16 जून, 1962 द्वारा पुराने क्षेत्रों पर विस्तारित किया गया है।

1	2	3	4
10.	1949	30	अन्तरित राज्य क्षेत्रों में यथा प्रवृत दा ईस्ट पंजाब ड्रग्ज कन्ट्रोल एक्ट, 1949.
11.	2008 वि0 सं0	1	भूतपूर्व पप्सू रियासत के पहले समाविष्ट क्षेत्रों में जो अब दा पंजाब रीआरगेनाइजेशन एक्ट, 1966 की धारा 5 के अधीन हिमाचल प्रदेश में जोड़ दिए गए हैं प्रवृत दा पैप्सू कोर्ट आफ वार्डज एक्ट, 2008 वि0 सं0।
12.	1956	38	अन्तरित राज्य क्षेत्रों में यथा प्रवृत दा पंजाब सपैशल पावरज़ (प्रैस) एक्ट, 1956.
13.	1957	18	अन्तरित राज्य क्षेत्रों में यथा प्रवृत दा पंजाब कोर्ट आफ वार्डज़ (वैलीडेशन आफ एक्सरसाईज आफ पावरज) एक्ट, 1957.
14.	1960	39	अन्तरित राज्य क्षेत्रों में यथा प्रवृत दा पंजाब प्राइमरी एजुकेशन एक्ट, 1960.
15.	1963	38	अन्तरित राज्य क्षेत्रों में यथा प्रवृत दा पंजाब स्टेट फैकल्टी आफ आयुर्वेदिक एण्ड यूनानी सिस्टम आफ मैडीसिन एक्ट, 1963.

उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

प्रथम नवम्बर, 1966 से पूर्व कालिक पंजाब राज्य के पुनर्गठन पर हिमाचल प्रदेश को पहाड़ी क्षेत्रों के अन्तरण के परिणामस्वरूप हिमाचल प्रदेश में कतिपय विषयों पर दो प्रकार की विभिन्न विधियां प्रवृत हैं। एकरूपता लाने के उद्देश्य से अधिनियमिति (विधेयक की अनुसूची-I में विनिर्दिष्ट) जो पुराने क्षेत्रों में पवत है, को उक्त पनर्गठन के परिणाम-स्वरूप हिमाचल प्रदेश को अन्तरित क्षेत्रों को प्रसारित करना तथा वहां प्रवृत सदृश अधिनियमिति को निरसित करना उचित समझा गया है।

कतिपय ऐसे अधिनियम हैं, (जैसा कि इस विधेयक की अनुसूची–II में विनिर्दिष्ट है) जिन की और अब आवश्यकता नहीं है। क्योंकि या तो इन की हिमाचल प्रदेश में उपयोगिता नहीं है या अप्रयुक्त हो गये हैं। 1825 के अधिनियम संख्या –11, 1920 के 1, 1941 के 5, 1949 के 30 तथा 1963 के 38 ने वर्तमान संदर्भ में अपनी उपयोगिता खो दी है। 1931 के अधिनियम संख्या –2 अर्थात् पंजाब म्युनिसिपल एक्जी-क्युटिव आफिसर्ज एक्ट, 1931 यद्यपि पंजाब रिआरगानाइजेशन एक्ट, 1966 की धारा 88 के कारण अन्तरित राज्य क्षेत्रों में प्रयोज्य है को केवल शिमला नगरपालिका सीमाओं के अन्दर प्रवृत किया गया था। हिमाचल प्रदेश म्युनिसिपिल कार्पोरेशन एक्ट, 1979 (1980 का 9) के प्रारम्भ के पश्चात् इस अधिनियमिति को प्राविधान पुस्तक में बनाये रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। पंजाब डैटर्ज प्रोटैक्शन एक्ट, 1936 (1936 का 2) जिसे पंजाब अधिनियम, 1938 की संख्या 9 द्वारा संशोधित किया गया था को हिमाचल प्रदेश डैट रिडकशन एक्ट, 1976 की धारा 30 के अधीन इस की प्रयोज्यता को निर-सित कर दिया गया है। चूंकि मूल अधिनियम इस राज्य में अब प्रवृत नहीं है, संशोधन अधिनियम अर्थात् 1938 का अधिनियम संख्या 9 को भी प्रविधान पुस्तक से हटाया जाना आवश्यक है। पूर्वी पंजाब इलैक्ट्रीसिटी (एमरजैंसी पावरज) एक्ट, 1941 (1941 का 14) जो आपात्त कालीन मामलों में सार्वजनिक विद्युत सेवाओं के संरक्षण की व्यवस्था करता है, केवल अन्तरित राज्य क्षेत्रों में प्रवृत्त है। इस राज्य में कोई सार्व-जनिक विद्युत सेवा उपक्रम नहीं है तथा हमारे प्रदेश में विद्युत की आपूर्ति, उत्पादन तथा वितरण के संपूर्ण कृत्य हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा निभाये जा रहे हैं। इस के अतिरिक्त इस अधिनियम में सम्मिलित बहुत से उपबन्ध इलैक्ट्रीसिटी (सप्लाई) एक्ट, 1948 तथा इण्डियन इलक्ट्रीसिटी एक्ट, 1910 के अन्तर्गत पहले ही समाविष्ट हैं। इसी प्रकार ईस्ट पंजाब मोलैसिज कन्ट्रोल एक्ट, 1948 इस प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न उपान्तरणों के साथ प्रवृत्त है। इस के अतिरिक्त केन्द्रीय मोलैसिज आर्डर, 1961 में भी सदृश उपबन्ध बनाये गये हैं। इस लिये पंजाब अधिनियम (1948 का 11) को हिमाचल प्रदेश राज्य में इस की प्रयोज्यता को निरसित करना आवश्यक हो गया है। पंजाव कोर्ट आफ वार्ड एक्ट, 1903 की हिमाचल प्रदेश राज्य में प्रयोज्यता हिमाचल प्रदेश अधिनियम, 1978 की संख्या 26 के अधीन निरसित कर दी गई है। परन्तु 2000 वि० सं० का पैप्सू एक्ट संख्या 1 तथा 1957 का पंजाब एक ट संख्या 18 अभी भी प्रविधान पुस्तक में हैं। इन को बनाये रखने की अब और आवश्यकता नहीं है। पंजाव स्पैशल पावरज (प्रैस) एक्ट, 1956 (1956 का 38) समाचार-पत्रों या पाक्षिकों के प्रकाशन के अभिवेचन तथा नियंत्रण की व्यवस्था करता है, तथा केवल अन्तरित क्षेत्रों में प्रवृत है। अनुवर्ती केन्द्रीय अधिनियमिति अर्थात् प्रिवेन्शन आफ पब्लिकेशन आफ ओवजक्शनेवल मैटर्ज एक्ट, 1976 सेन्सर कार्य अथवा प्रकाशन की

प्रविशिष्टी के निषेध की व्यवस्था नहीं करता है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुये कि पंजाब अधिनियम के प्रावधान केन्द्रीय अधिनियम के प्रावधान के विपरीत हैं, सरकार ने पंजाब अधिनियम की इस राज्य में प्रयोज्यता को निरसित करने का फैसला किया है।

विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति करने की व्यवस्थता करता है।

राम लाल,
मुख्य मंत्री।

शिमला :
दिनांक 23, मार्च, 1981

वितीय ज्ञापन

शून्य

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

विधेयक का खण्ड 7 विधेयक की अनुसूची-I में विनिर्दिष्ट अधिनियमिति की प्रयोज्यता को, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा 5 के अन्तर्गत अन्तरित क्षेत्रों में सुविधाजनक बनाने हेतु राज्य सरकार तथा इसके अधिकारियों को नियम, विनियमन बनाने तथा अधिसूचनाएं, आदेश एवं उप-विधियां जारी करने के लिए सशक्त करता है। प्रस्तावित प्रत्योयोजन अनिवार्य और प्रकृति में सामान्य है।

[Authorised English text of the Himachnl Pradesh Vidhi Vistaran Tatha Nirsan Vidheyak, 1981, as required under Article 348 (3) of the Constitution of India].

Bill No. of 3 1981.

THE HIMACHAL PRADESH EXTENSION OF LAWS AND REPEALING BILL, 1981

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

to provide for the extension of certain laws as applicable to, or in force in, the areas as comprised in Himachal Pradesh immediately before the 1st November, 1966, to areas as added to Himachal Pradesh under section 5 of the Punjab Re-organisation Act, 1966 and the repeal of certain enactments in their application to the State of Himachal Pradesh.

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Thirty-second Year of the Republic of India as follows:—

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Himachal Pradesh Extension of Laws and Repealing Act, 1981.

(2) It shall come into force at once.

Definitions.

2. In this Act, unless there is anything repugnant in the subject or context,—

(*a*) 'Official Gazette' means the Rajpatra, Himachal Pradesh;
(*b*) 'old areas' means the areas as comprised in Himachal Pradesh immediately before the 1st November, 1966;
(*c*) 'Schedule' means a schedule appended to this Act;
(*d*) 'State Government' means the Government of Himachal Pradesh; and
(*e*) 'transferred territories' means the territories which were added to Himachal Pradesh under section 5 of the Punjab Re-organisation Act, 1966.

Extension of certain laws to transferred territories.

3. The enactment, as amended from time to time, specified in Schedule I, which is applicable to, or is in force in, the old areas and all rules, regulations, notifications, orders and bye-laws made, and all directions or instructions issued, thereunder, which are in force immediately before the commencement of this Act, are hereby extended to, and shall be in force in, the transferred territories.

Construction of certain references.

4. In the enactment, or rules, regulations, notifications, orders and bye-laws made, and directions, or instructions issued, thereunder, as referred to in section 3, any reference—

(1) to the law which are not in force in the transferred territories shall, in relation to such territories, be construed as a reference to the corresponding law, if any, in force in such territories; and

(2) to the State of Himachal Pradesh, by whatever form of words, shall be construed as including a reference to the transferred territories.

Repeal and savings.

5. If, immediately before the commencement of this Act, there is in force in the transferred territories any law corresponding to the enactment or any of the rules, regulations, notifications, orders and bye-laws made, and directions or instructions issued, thereunder, extended to those territories by section 3 that law including the enactments specified in Schedule II, shall, on the commencement of this Act, save as otherwise expressly provided in this Act, stand repealed:

Provided that such repeal shall not affect,—

(*a*) the previous operation of any law so repealed or anything duly done or suffered thereunder, or

(*b*) any right, privilege, obligation or liability acquired, accrued or incurred under any law so repealed, or

(*c*) any penalty, forfeiture or punishment incurred in respect of any offence committed against any law so repealed, or

(*d*) any investigation, legal proceeding or remedy in respect of any such right, privilege, obligation, liability, penalty, forfeiture or punishment, as aforesaid,

and any such investigation, legal proceeding or remedy may be instituted, continued or enforced, and any such penalty, forfeiture or punishment may be imposed, as if this Act had not been passed:

Provided further that anything done or any action taken under any law so repealed shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provision of the enactment extended by section 3 to the transferred territories and shall continue to be in force accordingly, unless and until superseded by anything done or any action taken under the enactment so extended.

Powers of courts and other authorities for purposes of facilitating the application of the enactment specified in Schedule I or rules, etc.

6. For the purposes of facilitating the application in the transferred territories of the enactment specified in Schedule I or of any rule, regulation, notification, order, bye-law, direction or instruction referred to in section 3, any court or other authority may construe the same with such alterations, not affecting the substance, as may be necessary or proper to adopt it to the matter before the court or other authority.

Power to make rules, etc. not be affected.

7. Nothing contained in this Act shall affect the power of the State Government or of any officer or authority, exercisable under the enactment specified in Schedule I, to add, amend, vary or rescind the rules, regulations, notifications, orders and bye-laws made, and directions or instructions issued, as extended by section 3 to the transferred territories.

Power to remove difficulties.

8. If any difficulty arises in giving effect, in the transferred territories, to the provisions of the enactment specified in Schedule I, the State Government may, by order notified in the Official Gazette, make such provisions or give such directions as appear to it to be necessary or expedient for the removal of the difficulty.

SCHEDULE I

(*See* section 3)

Serial No.	Year	Number of Act	Name of the Act
1	2	3	4
1.	1953	7	The Himachal Pradesh Compulsory Primary Education Act, 1953.

SCHEDULE II

(*See* section 6)

Serial No.	Year	Number of Act	Name of the Act
1	2	3	4
1.	1825	11	The Bengal Alluvion and Diluvion Regulation, 1825 as in force in the transferred terr itories.
2.	1920	1	The Punjab Limitation (Custom) Act, 1920, as in force in the transferred territories.
3.	1920	1	The Punjab Limitation (Custom) Act, 1920, as applied to the erstwhile princely State of Bilaspur.
4.	1931	2	The Punjab Municipal (Executive Officers) Act, 1931 as in force in the transferred territories.
5.	1938	9	The Punjab Debtor's Protection (Amendment) Act, 1938, as in force in the transferred territories.
6.	1941	5	The Punjab Jagirs Act, 1941, as in force in the transferred territories.
7.	1941	14	The East Punjab Electricity (Emergency Powers) Act, 1941, as in force in the transferred territories.
8.	1948	11	The East Punjab Molasses (Control) Act, 1948, as in force in the transferred territories.
9.	1948	11	The East Punjab Molasses (Control) Act, 1948, as extended to the old areas by Government of India, Ministry of Home Affairs, notification No. F. 4/7/61-Jud.-II., dated the 16th June, 1962.
10.	1949	30	The East Punjab Drugs Control Act, 1948, as in force in the transferred territories.
11.	2008BK	1	The Pepsu Court of Wards Act, 2008 BK as in force in the areas which previously comprised in the erstwhile princely State of PEPSU and as now stands added to Himachal Pradesn under section 5 of the Punjab Re-organisation Act, 1966.
12.	1956	38	The Punjab Special Powers (Press) Act, 1956, as in force in the transferred territories.
13.	1957	18	The Punjab Court of Wards (Validation of Exercise of Powers) Act, 1957, as in force in the transferred territories.
14.	1960	39	The Punjab Primary Education Act, 1960, as in force in the transferred territories.
15.	1963	38	The Punjab State Faculty of Ayurvedic and Unani System of Medicines Act, 1963, as in force in the transferred territories.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

As a result of the transfer of hilly areas to Himachal Pradesh on the re-organisation of the erstwhile State of Punjab with effect from the 1st November, 1966, there have been in force in Himachal Pradesh two different laws on certain subjects. With a view to bringing about uniformity, it has been considered proper to extend the enactment (specified in the Schedule I to the Bill), as in force in the old areas, to the areas transferred to Himachal Pradesh as a result of the said re-organisation and to repeal the corresponding enactment, as in force there.

There are certain Acts (as specified in the Schedule II to this Bill) which are no longer required either because these have no utility in Himachal Pradesh, or have become obsolete. Act No. 11 of 1825, 1 of 1920, 5 of 1941, 30 of 1949 and 38 of 1963, in the present context have lost their utility. Act No. 2 of 1931 *i.e.* the Punjab Municipal (Executive Officers) Act, 1931, though is applicable in the transferred territories by virtue of section 88 of the Punjab Re-organisation Act, 1966, had been enforced only within the Simla municipal limits. After the commencement of the Himachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1979 (9 of 1980), there is no need to retain this enactment on the Statute Book. The Punjab Debtor's Protection Act, 1936 (2 of 1936), which was amended by the Punjab Act No. 9 of 1938, has been repealed in its application *vide* section 30 of the Himachal Pradesh Debt Reduction Act, 1976. Since the principal Act is no longer in force in this State, the Amendment Act *i.e.* the Act No. 9 of 1938, is also required to be removed from Statute Book. The East Punjab Electricity (Emergency Powers) Act, 1941 (14 of 1941), which provided for the protection of the public electricity services in cases of emergency, is in force only in the transferred territories. There are no public electricity service undertakings in this Pradesh and the entire functions of supply, generation and distribution of electricity in our Pradesh are being discharged by the Himachal Pradesh State Electricity Board. Besides this most of the provisions contained in this Act, already stand covered under the Electricity (Supply) Act, 1948, and the Indian Electricity Act, 1910. Similarly, the East Punjab Molasses (Control) Act, 1948, is in force in the different areas of this Pradesh with different modifications. All the more the Central Molasses (Control) Order, 1961 also makes the corresponding provisions. As such it has become necessary to repeal the Punjab Act (11 of 1948) in its application to the State of Himachal Pradesh. The Punjab Court of Wards Act, 1903, has been repealed in its application to the State of Himachal Pradesh *vide* Himachal Pradesh Act No. 26 of 1978. But the Pepsu Act No. 1 of 2008 B.K. and the Punjab Act No. 18 of 1957, still exist on the Statute Book. These are no longer required to be retained. The Punjab Special Powers (Press) Act, 1956 (38 of 1956) provides for the censor and control of publication of newspapers or periodicals, and is in force only in the transferred areas. The subsequent central enactment *i.e.* the Prevention of Publications of Objectionable Matters Act, 1976, does not provide for censorship or banning of entry of publication. In view of the fact that the Punjab Act is in conflict with the central Act, the Government have decided to repeal the Punjab Act in its application to this State.

The Bill seeks to achieve the aforesaid objections.

SIMLA:
The 23rd March, 1981.

RAM LALL,
Chief Minister.

FINANCIAL MEMORANDUM

Nil

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

Clause 7 of the Bill, empowers the State Government and its officers, to make the rules, regulations or to issue notifications, orders and bye-laws for facilitating the extension of the enactment specified in Schedule I of the Bill to the transferred territories. This delegation is essential and normal in character.

शिमला-171004, 24 मार्च, 1981

संख्या-1-11/81-वि0 स0--हिमाचल प्रदेश विधान सभा प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 135 के अन्तर्गत दा हिमाचल प्रदेश टाउन एण्ड कन्ट्री प्लानिंग (अमैण्डमैण्ट) बिल, 1981 (बिल नं0 7 आफ 1981) जो हिमाचल प्रदेश विधान सभा में 23 मार्च, 1981 को पुरःस्थापित किया गया है, सर्व साधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने के लिए प्रेषित किया जाता है।

राज कुमार महाजन,
सचिव।

Bill No. 7 of 1981

THE HIMACHAL PRADESH TOWN AND COUNTRY PLANNING (AMENDMENT) BILL, 1981

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

to amend the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 *(Act No.* 12 *of* 1977).

BE it enacted by the Himachal Pradesh Legislative Assembly in the Thirty-second Year of the Republic of India as follows :—

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Himachal Pradesh Town and Country Planning (Amendment) Act, 1981.

(2) It shall come into force at once.

Amendment of section 16.

2. In section 16 of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 (hereinafter called the principal Act),—

12 of 1977

(*i*) for the sign "." occurring at the end of clause (*b*) the sign ";" shall be substituted; and

(*ii*) after clause (*b*) so amended the following clause (*c*) shall be added, namely:—

"(*c*) no Registrar or the Sub-Registrar, appointed under the Indian Registration Act, 1908, shall, in any planning area constituted under section 13, register any deed or document of transfer of any sub-division of land by way of sale, gift, exchange, lease or mortgage with possession, unless the sub-division of land is duly approved by the Director, subject to such rules as may be framed in this behalf by the State Government:

16 of 1908

Provided that the Registrar or the Sub-Registrar may register any transfer,—

(*i*) where the land is owned by a person and the transfer is made without involving any further divisions;

(*ii*) where the partition/sub-division of land is made in a Joint Hindu Family;

(*iii*) where the lease is made in relation to a part or whole of a building ;

(*iv*) where the mortgage is made for procuring the loans for construction or improvements over the land either

from the Government or from any other financial institution constituted or established under any law for the time being in force or recognised by the State Government."

Amendment in section 32.

3. For the word "Commissioner" occurring in sub-section (1) of section 32 of the principal Act, the word "Secretary" shall be substituted.

Repeal and savings.

4. The Himachal Pradesh Town and Country Planning (Amendment) Ordinance, 1980, is hereby repealed. 4 of 1980

Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken or purporting to have been done or taken in exercise of any power conferred by or under the said Ordinance, shall, so far as it is not inconsistent with the provisions of this Act, be deemed to have been done or taken under this Act, as if this Act was in force on the day when such thing was done or action was taken.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

A large number of un-authorised sub-division of land is taking place in planning areas constituted under section 13 of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 (12 of 1977) unabated thereby creating un-planned layouts of land which may create slum, when built upon. As there exists no provision to check the sub-division which tends to mushroom growth and un-planned development, it has become necessary to make suitable amendments in the said Act.

Since the State Legislature was not in session and the matter was of urgent public importance calling for immediate action, the Governor of Himachal Pradesh after procuring the instructions of the President and in exercise of the powers vested in him under Article 213 of the Constitution of India, promulgated the Himachal Pradesh Town and Country Planning (Amendment) Ordinance, 1980 (Ordinance No. 4 of 1980) on the 6th November, 1980, published in the Rajpatra, Himachal Pradesh (Extraordinary) dated 12-11-1980. The said Ordinance is required to be replaced by a regular enactment.

Section 32 of the Act provides that an appeal under the Act can be preferred to an officer not below the rank of a Commissioner. At present there is no post of a Commissioner in the Public Works Department. As such it has become necessary to substitute the word "Commissioner" with the word "Secretary" in the aforesaid section.

This Bill seeks to replace the said Ordinance with modifications.

SIMLA:
The 23rd March, 1981.

RAM LALL,
Chief Minister.

FINANCIAL MEMORANDUM

Nil

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

Clause (*c*) of section 16 of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977, as proposed to be amended under clause 2 of Bill empowers the State Government to frame the rules. The rules so framed shall, after these are made, be laid before the Legislative Assembly. This delegation is essential and normal in character.

STATEMENT OF CIRCUMSTANCES NECESSITATING THE VARIATIONS IN THE HIMACHAL PRADESH ORDINANCE NO. 4 OF 1980

Section 32 of the Act provides that an appeal under the Act be preferred to an officer not below the rank of a Commissioner. At present there is no post of a Commissioner in the Public Works Department. As such it has become necessary to substitute the word "Commissioner" with the word "Secretary" in the aforesaid section. With this purpose a provision is provided to be inserted in clause 3 of the Bill.

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-3 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित ।